भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
***

दिसम्बर, 2020 के लिए मासिक सारांश

पंचायती राज मंत्रालय, संविधान के 73 वें संशोधन की निगरानी और कार्यान्वयन, परामर्शी कार्य के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से आरएलबी का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना और परामर्शी कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना।

माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ थी:

1. महीने के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आंध्र प्रदेश को पन्द्रहवें वित्त आयोग के बेसिक अबद्ध (अनटाइड) अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में 656.25 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की है।

2. इस महीने के दौरान, इस मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 17 राज्यों के लिए पन्द्रहवें वित्त आयोग की बद्ध (टाइड) अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में 11695.25 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की है। अनुशंसा के अनुसार राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.स.	राज्य	**सिफारिश किए गए बद्ध (टाइड) अनुदान की दूसरी किस्त** **(करोड़ रु.)**
1	बिहार	1254.50
2	छत्तीसगढ	363.50
3	गुजरात	798.75
4	हरियाणा	316.00
5	हिमाचल प्रदेश	107.25
6	झारखंड	422.25
7	कर्नाटक	804.25
8	केरल	407.00

9	मध्य प्रदेश	996.00
10	महाराष्ट्र	1456.75
11	ओडिशा	564.5
12	सिक्किम	10.50
13	तेलंगाना	461.75
14	त्रिपुरा	47.75
15	उत्तर प्रदेश	2438.00
16	उत्तराखंड	143.5
17	पश्चिम बंगाल	1103.00
	कुल	**11695.25**

3. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनटाइड एंड टाइड अनुदान की पहली किस्त 28 राज्यों को जारी कर दी गई है। जिन राज्यों ने पंचायतों / स्थानीय निकायों को अनुदान हस्तांतरित नहीं किया है, उन्हें पंचायतों को अनुदान हस्तांतरित करने और अनुदान हस्तांतरण प्रमाणपत्र (GTC) प्रस्तुत करने की दिशा में अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

4. पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग करते हुए पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों / गतिविधियों के सामाजिक ऑडिट के लिए एनआईआरडी और पीआर द्वारा तैयार सोशल ऑडिट दिशा निर्देशों के मसौदे पर चर्चा करने के लिए 22 दिसंबर, 2020 को सचिव, पंचायती राज (एसपीआर) की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) की बैठक आयोजित की गई। वीसी में एनआईआरडीपीआर के प्रतिनिधियों, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के राज्य पीआर विभागों और पंचायती राज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

5. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वर्ष 2020-21 के लिए संबंधित वार्षिक कार्य योजना की अनुमोदित गतिविधियों के लिए असम, मिजोरम, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को कुल 107.83 करोड़ रुपये जारी किए गए।

6. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य योजना (AAP) की समय पर तैयारी और प्रस्तुति सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को विस्तृत दिशा-निर्देश और चेक सूची जारी की गई।

7. आरजीएसए एमआईएस पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 दिसंबर, 2020 को अरुणाचल प्रदेश (एपी), गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश (एमपी), मेघालय, मणिपुर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था। ;

8. ब्लॉक विकास योजनाओं की तैयारी के लिए विभिन्न चरणों और समयसीमा की जानकारी देने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश राज्यों के लिए जारी किए गए।

9. सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनरों (एसएलएमटी) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 2 चरणों में एनआईआरडी एवं पीआर के साथ मिलकर ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए आयोजित किया गया था।

10. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय सख्ती से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) को अपनाने के लिए राज्यों पर जोर दे रही है। इस संबंध में, मंत्रालय राज्यों को ई-ग्रामस्वराज के साथ-साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायतों (जीपी) के पंजीकरण पूरा करने के लिए दबाव दे रहा है। वर्ष 2019-20 के लिए, 95% जीपी ने अपनी मंथ बुक बंद कर दी हैं और 95% ग्राम पंचायतों ने अपनी इयर बुक बंद कर दी हैं।

11. 1,69,951 ग्राम पंचायतों में ई-ग्राम स्वराज- पीएफएमएस इंटरफ़ेस उपलब्ध है, जिसमें से 1,03,961 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2019-20 के लिए 14 वें वित्त आयोग (एफसी) के तहत खर्च के लिए ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल (पूर्ववर्ती प्रियासॉफ्ट-पीएफएमएस इंटरफ़ेस (पीपीआई)) के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया है। राज्यों ने भी पंद्रहवें वें वित्त आयोग के तहत भुगतान करना शुरू कर दिया है। अभी तक 1,46,064 ग्राम पंचायतों ने पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत भुगतान शुरू किया है।

12. स्वामित्व योजना के तहत, जिसे 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण विधि द्वारा आबाद (आबादी) भूमि के सीमांकन के उद्देश्य से शुरू किया गया था और जारी करने के माध्यम से गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में रहने वाले ग्रामीण घरेलू मालिकों को 'अधिकार रिकॉर्ड' प्रदान किए गए थे, प्रॉपर्टी मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड, 25 जनवरी 2020 को भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 3 राज्यों के 749 गाँवों में वितरित किए गए । इसके अलावा, 14 दिसंबर, 2020 को अगले चरण की स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की तैयारियों के संबंध में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों के साथ अतिरिक्त सचिव, MoPR की अध्यक्षता में अनुवर्ती बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा, 15,329 गांवों में ड्रोन उड़ान पूरी हो चुकी है; जिसमें से 10,865 गाँवों के लिए सर्वेक्षण डेटा प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है और 8,366 गाँवों के लिए निकासी की सुविधा है। राज्यों में विभिन्न आईईसी गतिविधियां भी शुरू हुई हैं।

13. इसके अलावा, निचले स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने हेतु; मंत्रालय ने एक ऐप - ऑडिटऑनलाइन अंडर ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के तहत शुरू किया है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की अनुमति देता है और आंतरिक और बाहरी ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज करता है। राज्यों को ऑडिटऑनलाइन पर लाइव होने के लिए, राज्यों को कुछ जानकारी जैसे ऑडिट फ्लो, पदानुक्रम डेटा, जोखिम-आधारित श्रेणियां आदि प्रदान करनी होती है। यह जानकारी 25 राज्यों से प्राप्त हो चुकी है। 23 राज्यों ने 14 वें वित्त आयोग के खातों की ऑडिटिंग के लिए ऑडिटर्स (4,924 ऑडिटर रजिस्टर्ड) और ऑडिट प्लान (28,203 GPs) की तैयारी शुरू कर दी है। 22 राज्यों ने जीपी (ऑडिट) उपयोगकर्ता (1,48,199 ऑडिट) बनाने शुरू कर दिए हैं। दस राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तरप्रदेश ने भी इस पोर्टल पर अवलोकन (1,58,614 अवलोकन) दर्ज किए हैं। इसके अलावा, छह राज्यों ने ऑडिट रिपोर्ट (9,022 रिपोर्ट) तैयार की है।

14. अ.शा. पत्र दिनांक 1/12/2020 के द्वारा मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के YouTube चैनल (चैनल 1) पर अपलोड किए गए 102 ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रमों की एक अतिरिक्त सूची प्रदान की, जो राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के विभागों / निदेशालयों और पंचायती राज व ग्रामीण विकास राज्य संस्थान एवं पंचायती राज (SIRD & PRs) द्वारा अपने प्रभावी और बेहतर उपयोग के लिए आसान-से-पहुँच वेब-लिंक के साथ उपलब्ध है। इससे पहले, पंचायती राज मंत्रालय के मौजूदा YouTube चैनल (चैनल 2) पर उपलब्ध लगभग 300 ऑडियो-विजुअल कार्यक्रमों की एक सूची नवंबर 2020 माह के दौरान राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा की गई थी। इस प्रयास के लिए, मंत्रालय को हरियाणा के विकास और पंचायत विभाग से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। पंचायती राज मंत्रालय के YouTube चैनल पर व्यक्त किए गए विचारों की संख्या भी बढ़ गई है।

15. पंचायती राज मंत्रालय तीन प्रमुख कृषि कानूनों को लागू करने के बाद से सोशल मीडिया हस्तक्षेपों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों और किसान केंद्रित पहल के लाभों को उजागर करने के लिए नियमित रूप से कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की आईईसी गतिविधियों का समर्थन कर रहा है। पंचायती राज मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2020 को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसान परिवारों को वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करने से संबंधित और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के किसानों के साथ संबोधन / बातचीत का सोशल मीडिया पोस्ट / ट्वीट्स द्वारा प्रसार किया गया।

16. पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (24 दिसंबर 2020) के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड की ब्लॉक पंचायतों के साथ सचिव (उपभोक्ता मामले) की आभासी (वर्चुअल) बातचीत की सुविधा प्रदान की, जिसे वस्तुतः "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की नई विशेषताएं" थीम के साथ मनाया गया। इस संबंध में, पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए थे और ईमेल के माध्यम से ब्लॉक पंचायतों को वीसी लिंक प्रदान किया गया था। यह संदेश जो कि झारखंड के पंचायती राज और सभी ब्लॉक / मध्यवर्ती पंचायतों (पंचायत समिति) के मामलों से संबंधित था, झारखंड सरकार के अधिकारियों के बीच अल्पावधि में पहुंचाया गया। मंत्रालय ने झारखंड और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के बीच उपर्युक्त वेबिनार / वीसी के वेबकास्ट लिंक को बहु संदेश सेवा के माध्यम से प्रसारित किया।

17. वीसी के द्वारा बातचीत के दौरान, पंचायतों को उपभोक्ता ऐप सहित उपभोक्ताओं के सशक्तीकरण और जागरूकता के लिए उठाए गए कदमों और उपभोक्ता शिकायतों के समाधान में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और जोनल हेल्पलाइन द्वारा शिकायत निवारण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। पंचायतों को नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की कई अनूठी विशेषताओं के बारे में जागरूक किया गया और बताया गया कि ये कैसे उपभोक्ता के लिए फायदेमंद हैं और जागरूकता फैलाने और शिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां उपभोक्ता शोषण के लिए अधिक संभावनाएँ हैं। पंचायतों से अनुरोध किया गया था कि वे जन जागरूकता पैदा करने और कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायतों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कार्यक्रमों को लागू करने में अपना सक्रिय सहयोग दें।

18. वर्ष 2020 के दौरान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न आईईसी गतिविधियों में वर्ष 2020 के दौरान उपभोक्ता मामलों के विभाग की प्रमुख विशेषताओं में उल्लेख किया गया है [PIB के माध्यम से वर्ष के अंत में समीक्षा 2020 के रूप में जारी की गई]।

19. दिसंबर 2020 के महीने के दौरान, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोध के जवाब में, पंचायती राज मंत्रालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राम पंचायतों से अनुरोध किया कि वे अपने ग्राम पंचायतों में छात्रों और उनके माता-पिता, स्कूलों और कॉलेजों को सूचित करें कि आवेदन की अंतिम तिथि छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।

20. पंचायती राज मंत्रालय साप्ताहिक आधार पर देश भर की ग्राम पंचायतों को कोविड-19 सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन जन आन्दोलन अभियान पर भारी मात्रा में ग्रामीण जनता के बीच जागरूकता के लिए एसएमएस भेज रहा है, और बहु-एसएमएस के पांच दौर 3, 10, 17, 24 और 31 दिसंबर 2020 के दौरान भेजे गए थे। इसके अलावा, मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और MyGov कोरोना हब के पंचायती राज मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से जमीनी स्तर पर कोविड -19 के खिलाफ आम लड़ाई हेतु सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन जन आंदोलन पर आईईसी सामग्रियों को शेयर / रीट्वीट / रीपोस्ट करना जारी रखा।

21. त्रैमासिक पत्रिका ग्रामोदय संकल्प के आठवें अंक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों को अंतिम रूप दे दिया गया है, और अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों का प्रेषण शुरू हो गया है क्योंकि अन्य भाषा-संस्करणों का पुनरीक्षण चल रहा है।

22. मंत्रालय के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए RT-PCR परीक्षण आयोजित करने के लिए 4 दिसंबर 2020 को मंत्रालय परिसर में कोविड-19 परीक्षण शिविर का दूसरा दौर आयोजित किया गया। कोविड -19 कार्यस्थल के दिशा-निर्देश / प्रोटोकॉल / नियमित सफाई / स्वच्छता और कीटाणुशोधन उपायों को मंत्रालय परिसर में कोविड-19 के खिलाफ भारत के सामूहिक प्रयासों के रूप में पालन किया गया।

23. निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए गए:

(i) 30 दिसंबर, 2020 को सेवा के लिए एक आभासी (वर्चुअल) पुरस्कार समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया अवार्ड्स -2010 के उत्कृष्ट उत्पाद श्रेणी के तहत भारत के पंचायती राज मंत्रालय को माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित डिजिटल इंडिया गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया यह पुरस्कार मेटाडाटा आधारित सर्विस डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म सर्विसप्लस के लिए प्रदान किया गया जो कि- ईपंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत विकसित एक ऐप है।

(ii) पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप व नवाचारों का लाभ उठाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय और गैर-लाभकारी संगठन व्हील्स चैरिटेबल फाउंडेशन, जिसमें IIT के पूर्व छात्र शामिल हैं, के बीच 30 दिसंबर 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

24. विभिन्न राज्यों में सामुदायिक शौचालयों के मूल्यांकन के लिए 30.12.2020 को सचिव**,** पंचायती राज की अध्यक्षता में पंचायती राज मंत्रालय में यूनिसेफ द्वारा एक प्रस्तुति दी गई थी। अन्य प्रतिभागियों में कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के प्रतिनिधि और पंचायती राज मंत्रालय से वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

25. जल स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, शिक्षा, ग्रामीण आजीविका और स्थिरता के छह क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी को प्रभावित करने वाली चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने व्हील्स चैरिटेबल फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 30-दिसंबर, 2020 को हस्ताक्षर किए।

26. पंचायती राज मंत्रालय के आपदा प्रबंधन योजना पर चर्चा के लिए राज्यों के साथ 29.12.2020 को पूर्व विशेष सचिव डॉ बाला प्रसाद की अध्यक्षता में एक वीसी बैठक हुई। बैठक के दौरान, कर्नाटक, केरल, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पीआर विभागों के प्रतिनिधियों ने अपनी विषय वस्तु पर प्रस्तुति दी।

27. चल रहे / आने वाले त्योहारी सीजन के मद्देनजर, जागरूकता फैलाने और कोविड -19 से लड़ने के लिए जन आन्दोलन अभियान के तहत देश भर में पंचायतों / पीआरआई द्वारा विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ की गई। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज विभागों द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा भेजी गई सूचना / इनपुट के आधार पर साप्ताहिक रिपोर्ट, 4 दिसंबर, 2020 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दी गई है। जन आंदोलन अभियान के तहत राज्यों के पंचायती राज विभागों / पंचायतों / पीआरआई द्वारा की जाने वाली/ की जा रही गतिविधियों ने कोविड -19 से लड़ने के लिए विभिन्न पहल की, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

I. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत भवनों / प्रमुख स्थानों में कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए दीवार पेंटिंग, साइन बोर्ड, एलईडी डिस्प्ले, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर आदि का प्रदर्शन।

II. पंचायतों को अनुकूलित बल्क एसएमएस संदेश।

III. पीपुल्स प्लान कैम्पेन/ जन योजना अभियान के हिस्से के रूप में ग्राम सभा की बैठकों में प्रसार/ प्रचार।

IV. पंचायत पदाधिकारियों द्वारा डोर टू डोर अभियान

V. नियमित सार्वजनिक घोषणाएँ

VI. नुक्कड़ नाटक जैसी स्थानीय विकसित जागरूकता गतिविधियाँ

VII. सार्वजनिक स्थानों जैसे मंडी / बाज़ार आदि में प्रवेश का विनियमन।

VIII. ग्रामीण जन / क्षेत्रों और पंचायत प्रतिनिधियों / पदाधिकारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कोविड -19 संबंधित जागरूकता / संदेश पोस्ट करना।

28. संबंधित सम्मेलन के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के साथ चयनित ग्राम पंचायतों के लिए स्थानिक योजना रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से एनआरएससी और जीआईएस-एनआईसी की राज्य पंचायती राज विभागों की टीम और ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पांच बैठकें दिनांक 02.12.2020, 03.12.2020, 04.12.2020, 09.12.2020 और 24.12.2020 को आयोजित की गई। महीने के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव द्वारा निम्नलिखित स्थानिक योजना रिपोर्ट / प्रस्तुतियों की समीक्षा की गई: -

(i) झीट जीपी, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ के लिए स्थानिक योजना रिपोर्ट / प्रस्तुति एनआईटी रायपुर को प्रस्तुत किया।

(ii) मणिपाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, कर्नाटक द्वारा शंकरनारायण जीपी के लिए स्थानिक योजना रिपोर्ट / प्रस्तुति।

(iii) बेलाडा जीपी के लिए स्थानिक योजना रिपोर्ट / प्रस्तुति आईआईटी रुड़की, उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत की गई।

(iv) अगुबानी जीपी, पश्चिम बंगाल के लिए स्थानिक योजना रिपोर्ट / प्रस्तुति आईआईटी खड़गपुर द्वारा प्रस्तुत की गई।

(v) तारापुर जीपी, गुजरात के लिए स्थानिक योजना रिपोर्ट / प्रस्तुति, सीईपीटी, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा प्रस्तुत की गई।

(vi) तेलापरोलू जीपी, आंध्र प्रदेश के लिए स्थानिक योजना रिपोर्ट / प्रस्तुति स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत की गई।

(vii) कलौंडा जीपी, उत्तर प्रदेश के लिए स्थानिक योजना रिपोर्ट / प्रस्तुति, अपीजय स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत की गई।

(viii) बोंगसर जीपी, असम के लिए स्थानिक योजना प्रस्तुति आईआईटी गुवाहाटी द्वारा प्रस्तुत की गई।

(ix) नवलुर कोट्टापट्टू जीपी तमिलनाडु के लिए स्थानिक योजना रिपोर्ट / प्रस्तुति एनआईटी, त्रिची द्वारा प्रस्तुत की गई।

(x) भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, पुणे द्वारा राजुरी जीपी, महाराष्ट्र के लिए स्थानिक योजना रिपोर्ट / प्रस्तुत की गई।

29. 1 दिसंबर, 2020 के अनुसार मंत्रालय के पास 21 शिकायतें/ याचिकाएं लंबित थीं और 226 (यानी 200 ऑनलाइन + 26 भौतिक) शिकायतें/ याचिकाएं दिसंबर महीने के दौरान प्राप्त हुई थीं। कुल 247 में से (226 अक्टूबर में प्राप्त + 21 को पिछले महीने से आगे बढ़ाया गया), दिसंबर में 219 शिकायतों/ याचिकाओं का निपटारा किया गया और 18 को 1 जनवरी, 2021 को आगे बढ़ाया गया।

30. दिसंबर, 2020 के दौरान, ई-ऑफिस प्रणाली में 112 ई-फाइलें खोली गईं, जो महीने के दौरान खोली गई कुल फाइलों का 100% है।

Government of India

Ministry of Panchayati Raj

***

Monthly Summary for the month of November, 2020

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work.

The following were the main activities during the month:

1. During the month, Ministry of Panchayati Raj has recommended for release of Rs**. 656.25 crore** as second instalment of XV FC **Basic** (**Untied**) Grants for FY 2020**-**21 to Andhra Pradesh**.**

2. During the month, this Ministry has recommended for release of Rs**. 11695.25 crore**as second installment of XV FC **Tied Grants** for FY 2020**-**21 to 17 States**.** The State**-**wise detail of recommendation is as under**:**

Sl. No.	**State**	**Second Instalment of TiedGrants Recommended (Rs.Crore)**

1	Bihar	1254.50
2	Chhattisgarh	363.50
3	Gujarat	798.75
4	Haryana	316.00
5	Himachal Pradesh	107.25
6	Jharkhand	422.25
7	Karnataka	804.25
8	Kerala	407.00
9	Madhya Pradesh	996.00
10	Maharashtra	1456.75
11	Odisha	564.5
12	Sikkim	10.50
13	Telangana	461.75
14	Tripura	47.75
15	Uttar Pradesh	2438.00
16	Uttarakhand	143.5
17	West Bengal	1103.00
	Total	**11695.25**

3. The first instalment of XV FC Untied and Tied Grants for F.Y. 2020-21 have been released to 28 States. Follow up action have been carried out towards asking the States which have not transferred Grants to Panchayats/Local Bodies to transfer the Grants to the Panchayats and submit Grant Transfer Certificate (GTC) to the effect.

4. A VC meeting under the chairmanship of Secretary, Panchayati Raj (SPR) held on 22nd December, 2020 to discuss the draft Social Audit Guidelines prepared by NIRD&PR for conducting social audit of the XV FC mandated works/activities created by the Panchayats utilizing XV FC Grants. The VC was attended by the representatives from NIRDPR, State PR Departments of Andhra Pradesh, Jharkhand, Karnataka and Madhya Pradesh and Senior Officers from MoPR.

5. A total of Rs. 107.83 Crore were released to the states of Assam, Mizoram, Odisha, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal for the approved activities of the respective Annual Action Plan for 2020-21 under the scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA).

6. Detailed guidelines and check list issued to all States / UTs for ensuring timely preparation and submission of Annual Action Plans (AAPs) for the year 2021-22 under the scheme of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA).

7. A Training Programme on RGSA MIS was organized on 17th December,2020 for the nodal officers of State/UTs of Arunachal Pradesh (AP), Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Kerala, Madhya Pradesh (MP), Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana , Andaman and Nicobar Islands (A&N), Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (DNH & DD), Ladakh and Jammu and Kashmir (J&K).

8. A detailed advisory to states indicating various steps and timelines for preparation of Block Development Plans was issued.

9. Training Programme for State Level Master Trainers (SLMTs) of all States/ UTs were organized during 16th till 19th December in 2 Phases in coordination with NIRD&PR on preparation of Block Development Plans.

10. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing States for closure of account on eGramSwaraj as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS.

For the year 2019-20, 95% of the GPs have closed their month books and 95% of the Gram Panchayats have closed their year books.

11. 1,69,951 Gram Panchayats have on-boarded eGramSwaraj-PFMS interface, out of which 1,03,961 GPs have carried out online payments through the Online Payment Module (erstwhile PRIASoft-PFMS Interface (PPI)) for the expenditure incurred under 14th Finance Commission (FC) for 2019-20. States have also started carrying out payments under XV Finance Commission. As on date, 1,46,064 GPs have initiated payments under XV FC.

12. Under SVAMITVA Scheme that was launched on 24th April 2020 with the aim of demarcation of inhabited (Abadi) land in rural areas by drone survey method and conferring 'record of rights' to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages through issuance of property cards to the property owners, Property card has been distributed in 749 villages of 3 States on the occasion of birth anniversary of former Prime Minister of India, Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee on 25th Dec 2020. Also, follow-up meeting was held under Chairmanship of Additional Secretary, MoPR with States of Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Odisha, Tamil Nadu and Telangana regarding preparedness towards the implementation of next Phase SVAMITVA Scheme on 14th Dec 2020.Furthermore, drone flying has been completed in 15,329 villages; out of which data processing of survey data is completed for 10,865 villages and feature extraction for 8,366 villages. Various IEC activities have also commenced in States.

13. Further, strengthening the transparency and accountability at grassroots level; the Ministry has rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). It allows for online audit of Panchayat accounts and records detailed information about internal and external audit. For States to go live on AuditOnline, States are to provide pre-requisites viz. Audit flow, hierarchy data, risk-based categories etc. Information has been received from 25 States. 23 States have started registration of Auditors (4,924 Auditor registered) and preparation of Audit Plan (of 28,203 GPs) for

Auditing 14th Finance Commission accounts. 22 States have started creating GP (Auditee) users (1,48,199 Auditees). Ten States viz. Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Tripura and Utar Pradesh have also recorded Observations (1,58,614 observations) on the application. Also, Six States have generated audit reports (9,022 Reports).

14. Vide D.O. letter dated 1/12/2020 Ministry provided an additional list of 102 audio-visual programmes uploaded on MoPR's YouTube Channel (Channel 1) with easy-to-access web-link for its effective and better utilization by State/UT Departments/Directorates of Panchayati Raj and State Institutes of Rural Development &Panchayati Raj (SIRD&PRs). Prior to this, a list of around 300 audio-visual programmes available on MoPR's existing YouTube Channel (Channel 2) was shared with States/ UTs during the month of November 2020. To this endeavour, Ministry has received enthusiastic response from Development & Panchayats Department, Haryana. The number of views on MoPR's YouTube Channels has also been increased.

15. Ministry of Panchayati Raj has regularly been supporting the MoA&FW's IEC activities for highlighting the benefits of the recent reforms in the agriculture sector and farmer-centric initiatives through social media interventions since enactment of the three key agriculture laws. Ministry of Panchayati Raj disseminated the social media posts / tweets related to release of the next installment of financial benefit to 9 crore farmer families under PM KisanSammanNidhi on 25 December 2020 and Hon'ble Prime Minister's address / interaction with the farmers on this occasion.

16. The Ministry of Panchayati Raj facilitated virtual interaction of Secretary(Consumer Affairs) with Block Panchayats of Jharkhand through video conferencing on the occasion of National Consumer Day (24 December 2020), which was virtually celebrated with the theme "New Features of the Consumer Protection Act, 2019". In this regard, advisory was issued by the Department of Panchayati Raj, Government of Jharkhand and VC link was provided to Block Panchayats through email. This message was circulated amongst the State Government Officers of Jharkhand dealing with the

matters of Panchayati Raj and all the Block /Intermediate Panchayats (पंचायतसमिति) of Jharkhand at a short notice. Ministry circulated the webcast link of the aforesaid Webinar / VC among Panchayati Raj Institutions in Jharkhand and Uttar Pradesh through bulk messaging service.

17. During the VC interaction, Panchayats were informed about steps taken towards empowerment and awareness of consumers including Consumer App and the process of grievance redressal by National Consumer Helpline and Zonal Helplines in resolving consumer grievances. Panchayats were sensitised about the several unique features of the new Consumer Protection Act, 2019 and explained how these are advantageous to the consumer and importance of spreading awareness and educating, particularly those in rural areas where consumers are more susceptible to exploitation. Panchayats were requested to extend their active support in creating mass awareness and implementing the programmes through Common Service Centres, Panchayats and Krishi Vigyan Kendras.

18. Various IEC activities carried out by the Ministry of Panchayati Raj during 2020 have found mention in the major highlights of the Department of Consumer Affairs during the year 2020 [issued through PIB as Year End Review 2020].

19. During the month of December 2020, in response to request made by Ministry of Minority Affairs, the Ministry of Panchayati Raj requested Gram Panchayats through social media to inform the students and their parents, schools and colleges in their Gram Panchayats that the last date for application under Scholarship Schemes for students belonging to economically weaker sections of six notified minority communities (Buddhist, Christian, Jain, Muslim, Parsi and Sikh), has been extended up to 31st December 2020.

20. Ministry of Panchayati Raj has been sending bulk SMSes on COVID-19 Positive Behavioral Change Jan Andolan Campaign to Gram Panchayats across the country on weekly basis, and five round of bulk-SMSes were sent during the month of December

2020 – on 3rd, 10th, 17th, 24th and 31st December 2020 for awareness among the rural masses. In addition, Ministry continued to share/ retweet/ repost the IEC materials on Positive Behavioral Change Jan Andolan Campaign available on social media pages of Ministry of Health and Family Welfare and MyGov Corona Hub through Ministry of PanchayatiRaj's social media platforms to maintain the momentum of intensive common fight against COVID-19 at grassroots level.

21. Hindi and English versions of the eighth issue of quarterly magazine Gramoday Sankalp have been finalised, and printing, dispatch of the English and Hindi versions has startedas vetting of other language-versions are going on.

22. Second round of COVID-19 Testing Camp was organised in the Ministry premises on 4th December 2020 for conducting RT-PCR test for officers / employees of the Ministry. COVID-19 workplace guidelines / protocols / regular cleaning / sanitising and disinfection measures were scrupulously adhered to in the Ministry premises as part of India's collective against COVID-19.

23. The following important developments were also disseminated through social media:

(i) Conferring of the prestigious Digital India GOLD Award by Hon'ble President of India to the Ministry of Panchayati Raj under Exemplary Product category of the Digital India Awards–2020 via video conferencing in a virtual awards ceremony held on 30th December 2020 for ServicePlus – A metadata-based Service Delivery Platform – an application developed under ePanchayat Mission Mode Project, and
(ii) Signing of an MoU between Ministry of Panchayati Raj and WHEELS Charitable Foundation – Non-Profit Organization – comprising IIT Alumni on 30th December 2020 to leverage technology interventions and innovations to strengthen Panchayati Raj Institutions.

24. A presentation was given by UNICEF in the Ministry of Panchayati Raj under the chairmanship of Secretary, Panchayati Raj on 30.12.2020 regarding study for assessment of community toilets in various States. The other participants were representatives from Ministry of Skill Development & Entrepreneurship and seniors officers from MoPR.

25. Ministry of Panchayati Raj entered into Memorandum of Understating (MoU) with WHEELS Charitable Foundation, a Not-For-Profit Organisation on 30th December, 2020 for providing technology driven solutions to the challenges that affect rural population in the six areas of Water Healthcare, Energy, Education, Rural Livelihood and Sustainability.

26. A VC meeting under the chairmanship of Dr. Bala Prasad, Former Special Secretary was held on 29.12.2020 with States to discuss on Disaster Management Plan for Ministry of Panchayati Raj. During the meeting, representatives of PR Departments of Karnataka, Kerala, Gujarat and Uttar Pradesh gave their presentations on the subject matter.

27. In the wake of the ongoing / incoming festive seasons, various awareness activities were undertaken by the Panchayats / PRIs across the country under Jan Andolan Campaign to spread awareness and fight Covid-19. Weekly Report on the basis of information/inputs provided by the States/UTs regarding various activities undertaken / being taken by the States/UTs Panchayati Raj Departments, have been furnished on 4th December, 2020 by Ministry of Panchayati Raj to the Ministry of Information and Broadcasting. Activities which were undertaken by the States Panchayati Raj Departments/Panchayats/PRIs under Jan Andolan Campaign took various initiatives to fight Covid-19 included the following:

i. Display of wall paintings, sign boards, LED displays, hoardings, posters, banners etc. for Covid Appropriate behavior in Gram Panchayat Buildings/Prominent places in rural areas.

ii. Customised Bulk SMS Messages to Panchayats**.**

iii. Dissemination in Gram Sabha Meetings as part of People**'**s Plan Campaign **(**PPC**).**

iv. Door to Door Campaign by Panchayat functionaries

v. Regular Public Announcements

vi. Local developed awareness activities like Nukkad Dramas

vii. Regulation of entry to public places like Mandis**/**Bazaars etc**.**

viii. Posting of Covid**-**19 related awareness**/**messages on MoPR**'**s official Twitter Accounton regular basis for creating awareness in the rural masses **/**areas and panchayat representatives**/**functionaries**.**

28.Five meetings through Video Conference (VC) were held on 02.12.2020, 03.12.2020, 04.12.2020, 09.12.2020 & 24.12.2020, to discuss the Spatial Planning Reports for selected gram panchayats with active participation of representatives of concerned institutes, State Panchayati Raj Departments team of NRSC and GIS-NIC and senior officers from MoRD and MoPR. During the month, following Spatial Planning Reports/presentations were reviewed by the Secretary, Ministry of PanchayatiRaj:-

(i) Spatial Planning Report/presentation for Jheet GP, Distt.-Durg, Chhattisgarh. submitted The NIT Raipur

(ii) Spatial Planning Report/presentation for Shankarnarayana GP submitted by the Manipal School of Architecture and Planning, Karnataka.

(iii) Spatial Planning Report/presentation for Belada GP, Uttarakhand submitted by IIT, Roorkee.

(iv) Spatial Planning Report/presentation for Aguibani GP, West Bengal submitted IIT, Kharagpur

(v) Spatial Planning Report/presentation for Tarapur GP, Gujarat submitted by CEPT, Ahmedabad, Gujarat.

(vi) Spatial Planning Report/presentation for Telaprolu GP, Andhra Pradesh submitted by School of Planning & Architecture, Vijayawada, Andhra Pradesh.

(vii) Spatial Planning Report/presentation for Kalonda GP, Uttar Pradesh submitted by Apeejay School of Architecture & Planning, Greater Noida, Uttar Pradesh.

(viii) Spatial Planning presentation for Bongshar GP, Assam submitted by IIT Guwahati.

(ix) Spatial Planning Report/presentation for Navalur Kottapattu GP, Tamil Nadu submitted bt NIT, Trichy.

(x) Spatial Planning Report/presentation for Rajuri GP, Maharashtra submitted by BharatiVidyapeeth College of Architecture, Pune

29. There were 21 grievances/petitions pending with Ministry as on 1st December, 2020 and 226 (i.e. 200 online + 26 physical) grievances/ petitions were received during the month of December. Out of total 247 (226 received in October + 21 carried forward from last month), 219 grievances/petitions were disposed in December and 18 were carried forward as on 1st January, 2021.

30. During December, 2020, 112 e-files were opened in e-office system which constitutes 100% of the total files opened during the month.

****